

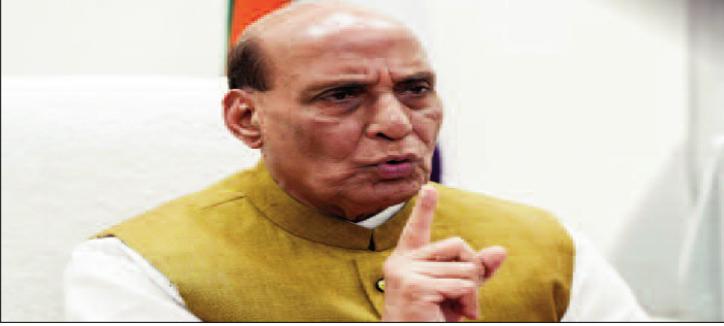
देश में एक समान कानून ही सच्ची एकता : अजित पवार



मुंबई (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के छह साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अंजित पवार ने इसे देश की एकता के लिए जरूरी कदम बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब हम एक ही देश में रहते हैं, तो जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले अलग-अलग राज्यों के लिए अलग कानून होना कई लोगों को स्वीकार नहीं था। अब समय आ गया है कि पूरे देश में एक समान कानून लागू हो, यही सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय एकता है। महायुति सरकार के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर पवार ने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार को जनादेश मिला है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हालिया कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और सरकार को प्राथमिकता महाराष्ट्र का विकास है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार केंद्र से अधिकतम सहयोग पाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अंजित पवार ने कहा कि किसी पर

ब्रह्मोस, एस-400 से लेकर बराक-1 तक, भारत की वॉर शील्ड बनेगी और भी मजबूत

67,000 करोड़ रुपये के नए रक्षा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी



नड़ दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। व्योकि भारत का पड़ोसी चीन रक्षा मामले में लगातार ताकतवार होता जा रहा है। चीन का ताकतवार होना भारत के लिए चिंता का विषय है। इसी चिंता को देखते हुए भारत सरकार ने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ रुपये के नए रक्षा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यह फैसला केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में लिया गया। इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़त तनाव के बीच भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत को बढ़ाना है। भारत अब किसी भी हाल में रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों से कमजोर नहीं रहना चाहता है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत, भारतीय सेनाओं के लिए कई महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर खरीदे जाएंगे।

भारतीय थल सेना के लिए टैकों
इस्तेमाल होने वाली थर्मल-इमेजर-आधारित
ड्राइवर नाइट-साइट की खरीद की जाएगी।
जिससे रात में युद्ध संचालन की क्षमता में सुधार
होगा। तीनों सेनाओं के लिए: तीनों सेनाओं वाले
लिए पीडीयम एल्टीटयूड लॉन्ग एंडीयरेस व
खरीद के साथ-साथ, रूस निर्मित एस-40
मिसाइल सिस्टम के वार्षिक रखरखाव के
कॉन्ट्रैक्ट को भी मंजूरी दी गई है। एस-40
मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में पाकिस्तान के
साथ हुए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
थी। डीएसी ने इसकी अहमियत को देखते हुए
मिसाइल सिस्टम के व्यापक सालाना मेंटेनेंस
कॉन्ट्रैक्ट को भी मंजूरी दी है। आर्मी के लिए
थर्मल-इमेजर-आधारित ड्राइवर नाइट-साइट
की खरीद के लिए शुरूआती मंजूरी दी गई है जिसके
तैकों में काम करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा विश्व
इससे बीएपी यानी की रात में संचालन की
क्षमता बढ़ेगी।

टर्ट की राहुल गांधी को फटकार,
भार ने किया समर्थन

- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उचित है और विपक्ष को अपनी भूमिका समझानी चाहिए

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओपी राजभर ने सुरोम कोट्ट द्वारा ग़हल गांधी को दी गई फटकार का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि सुरोम कोट्ट की इच्छणी पूरी तरह उचित है और विषयक को अपनी भूमिका समझना चाहिए। मंत्री राजभर ने कहा कि विषयक ने



**7 साल पहले शाह पर की गई¹
टिप्पणी के मामले में राहुल
गांधी को मिली जमानत**

रांची (एंजेसी)। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने काग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में अपरोप लगाया था कि उहने वर्ष 2018 में काग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। अब इस मामले में काग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में जमानत मिल गई है।

शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि काग्रेस में कई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। काग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है। इस शिकायत बाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती बाट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञन नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती बाट जारी किया था। यह मामला वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ बाट जारी करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें कई महीनों तक राहत मिली थी। मार्च, 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका निषादित कर दी। इसके बाद चाईबासा कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस मामले में कोर्ट में आवेदन दायितव्य कर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट की मांग की थी, लेकिन इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।

स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, माला
पहनाने के बहाने थप्पड़ जड़ा

निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर, मनसे ने दी सबक सिखाने की चेतावनी

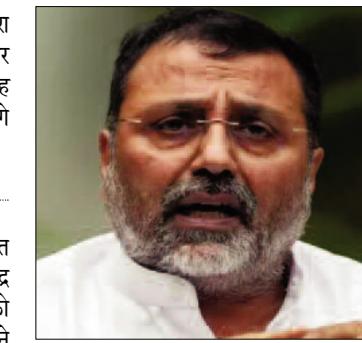
नासिक (एजेंसी)। महाराष्ट्र की जनता से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे माफ़ी मार्ग ऐसी मांग महाराष्ट्र नवर्नाण सेना (मनसे) ने की थी। हालांकि, जब सांसद दुबे ने माफ़ी नहीं मांगी, तो नासिक मनसे शहर अध्यक्ष सुदाम कोंबडे ने नासिक ज़िला न्यायालय में दुबे के ख़लाफ़ याचिका दायर की। साथ ही सांसद दुबे को मनसे शैली में सबक सिखाने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि सांसद दुबे ने मराठी समुदाय के ख़लाफ़ विवादाप्त बयान देने के लिए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना (यूटीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की थी। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मराठी लोग किसकी रोटी खाते हैं? तुम मराठी लोग हमारे पैसों पर पलते हो बला विवादाप्त बयान देने के बाद, महाराष्ट्र में उनके ख़लाफ़ गुस्से की लहर दौड़ गई थी। उधर मुर्बई से स्टे मीरा-भयंदर में एक प्रवासी दुकानदार के मराठी न बोलने की बात कहने पर मनसे कार्यकर्ताओंने उस पर हाथ डाया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ठाकरे बंधुओं पर तब हमला बोला था। निशिकांत दुबे ने मराठी लोगों पर तंज कसते हुए कहा था, बताओ मराठी लोग कितना बैक्स देते हैं। इस पर मनसे के नासिक शहर अध्यक्ष सुदाम कोंबडे ने चेतावनी दी थी कि दुबे महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मार्ग, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई का सामना करें। लेकिन इसके बाद भी सांसद दुबे ने इस मामले में माफ़ी नहीं मांगी। इसलिए सुदाम कोंबडे ने उनके ख़लाफ़ नासिक ज़िला सत्र न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 356 के तहत अवमानना याचिका दायर की है। मनसे शहर अध्यक्ष सुदाम कोंबडे ने यह भी चेतावनी दी है कि दुबे जब नासिक आएंगे तो उहाँसे सबक सिखाएंगे।

*** दुबे कोई बयान न दें**

मराठी मुद्दे पर दिए गए उनके विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को शांत रहने की सलाह दी है। देवेंद्र फडणवीस ने 4 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए कहा, हम महाराष्ट्र में स्थिति को संभालने में सक्षम हैं। मराठी लोग और यहाँके अमराठी भी सुरक्षित हैं। प्रदानाम से पापारी और पापारी के बीच लोर्ड

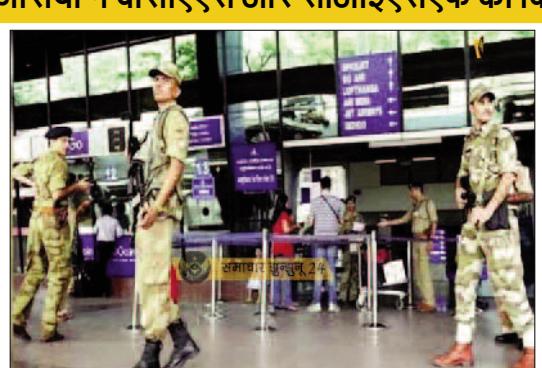
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एलिवश के खिलाफ द्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने एलिवश यादव को सांप के जहर से जुड़े मामले में चल रही द्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप-पत्र और आपराधिक कार्यवाही के चुनौती देने वाली एलिवश की याचिका पर यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है। बता दें इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एलिवश यादव की याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दायर आरोप-पत्र के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया था उनके खिलाफ रेव पार्टियों का आयोजन और विदेशियों को आमत्रित करने के आरोप भी शामिल हैं जो लोगों को सांप के जहर और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। जरिट्स सौभर श्रीवास्तव की पीठ ने मई में उनकी याचिका खारिज करते हुए मौखिक टिप्पणी की थी कि एलिवश के खिलाफ आरोप-पत्र और एफआईआर में बयान दर्ज हैं और मुकदमे के दौरान ऐसे आरोपों की सत्यता की जांच की जाएगी। पीठ ने यह भी कहा कि एलिवश ने याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है। इसके बाद अब यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्प्लाइएंसर एलिवश को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दूसरे ग्राह दी स्पष्टीय कोर्ट ने जोनेटिप्प भी जारी किया है। एलिवश ने रेत पार्टी में ग्राह का टार्गेट करने के मामले में गैरीजनाबाद कोर्ट में टायर चार्टर्सीट तो चुनौती दी है।



सितंबर-अक्टूबर के बीच देश के एयरपोर्ट पर हो सकता है आतंकी हमला

खुफिया एजेंसियों ने बीसीएएस और सीआईएसएफ को किया अलर्ट



साथ मिलकर काम करने को कहा है। आगर कोई नई जानकारी या अलर्ट प्रिलिंग है, तो उसे तुरत सभी संबंधित पक्षों के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए बीसीएस ने कई सख्त कदम उठाने के लिए भी कहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद, बुहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सार्वजनिक स्थानों और कबूतरखानों में दाना डालने पर सख्ती से रोक लगा दी है। कोर्ट का तर्क है कि कबूतरों की बढ़ती आबादी से श्वसन संबंधी बीमारियाँ फैल रही हैं और ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान हो रहा है।



मंगल प्रभात लोढ़ा ने नगर आयुक्त को तत्काल समाधान के तौर पर

बीसीएस ने एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी स्टाफ, कॉटेक्टर और आगंतुकों की पहचान करने को कहा है। इसके अलावा सभी यात्री कैमरों को लगातार चालू रखने और निगरानी करने के आदेश दिए हैं। ग्रे की पहचान कर खराब कैमरों को सही कैमरे के निर्देश भी दिए हैं। बीएसएस का यह न केवल एयरपोर्ट, बल्कि एयरलाइंस अन्य विमानन सेवाओं से जुड़े सभी यात्रियों पर भी लागू होगा। घरेलू और विदेशी यात्राओं में सापान और कूपरे वी

यह प्रतिबंध विशेष रूप से जैन और गुजराती समुदाय के लिए एक संवेदनशील धार्मिक मुद्दा बन गया है। जैन धर्म में कबूतरों को दाना खिलाना करुणा और अहिंसा का प्रतीक बताया जाता है, जो उनकी सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जैन धर्मगुरु नरेशचंद्र जी महाराज ने आमरण अनशन की घोषणा की है, और हजारों लोगों ने कोलाबा से गेटवे ऑफ इंडिया तक विरोध मार्च निकाला है। विवाद ने अब गुजराती विधि पत्र लिखकर प्रतिबंध पर फिर से विचार करने मांग की है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि क्या केवल कबूतरों को दाना डालना ही जनस्वास्थ्य संकट का एकमात्र कारण है। इसके बाद अब मुंबई प्रशासन के लिए जनस्वास्थ्य और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहाँ न्यायालय का निर्णय वैज्ञानिक और स्वच्छता के दृष्टिकोण से सही लगता है, वहाँ आदेश को लागू करते समय सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। यह मामला अब सिफर एक आदत नहीं, बल्कि धार्मिक अधिकार, प्रशासनिक आदेश, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच दीपी पानी की

कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक का मामला बना धार्मिक आस्था और जनस्वास्थ्य के बीच टकराव का कारण

यह प्रतिबंध विशेष रूप से जैन और गुजराती समुदाय के लिए एक स्वेदनशील धार्मिक मुद्दा बन गया है। जैन धर्म में कबूतरों को दाना खिलाना करुणा और अहिंसा का प्रतीक बताया जाता है, जो उनकी सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। बाँधे हाईकोर्ट के अदेश के खिलाफ जैन धर्मगुरु नरेशचंद्र जी महाराज ने आमरण अनशन की घोषणा की है, और हजारों लोगों ने कोलाबा से गेटवे ऑफ इंडिया तक विरोध मार्च निकाल दिया है। विवाद ने अब गज़नीतिक तत्त्वानुसारी लोगों के लिए एक अतिरिक्त स्थानीय निकायों को नियंत्रित और स्वच्छ कबूतरखानों की योजना बनाने का चाहीए। इससे धार्मिक परंपरा भी बर्बाद रहेगी और नागरिकों के स्वास्थ्य पर धर्म कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मुंबई जैसे बहुपाल्स्कृतिक शहर में, किसी भी निर्णय का लागू करते समय सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहाँ न्यायालय का निर्णय वैज्ञानिक और स्वच्छता के दृष्टिकोण से सही लगता है, वहीं अदेश ने ज्ञान वाले सामाजिक वैज्ञानिकों का नियंत्रित लापता करने की विरोधी विवादों को नियंत्रित किया है। इससे धार्मिक परंपरा भी बर्बाद रहेगी और नागरिकों के स्वास्थ्य पर धर्म कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मुंबई जैसे बहुपाल्स्कृतिक शहर में, किसी भी निर्णय का लागू करते समय सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। यह मामला अब तक सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि धार्मिक अधिकार, प्रशासनिक अदेश, और सार्वनियन् लापता के बीच दोनों

अलर्टः असम विहार उत्तराखण्ड और भूतान्त्रियों में गंभीर हादू की स्थिति

नई दिल्ली(एजेंसी)। असम के हैलाकांडा जिले में धलेश्वरी नदी(धारमुरा) सुबह 6:00 बजे 29.74 मीटर पर थी, जो खतरे के निशान (28.05 मीटर) से 1.69 मीटर ऊपर है। इसी जिले में कर्खल नदी (मतिजुरी) 20.73 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान (20.27 मीटर) से 0.46 मीटर ऊपर है। तिनसुकिया जिले में बुरिदेहिंग नदी (मार्गेण्टा) 134.55 मीटर पर है, जो खतरे के निशान (134.42 मीटर) से थोड़ा ऊपर है। इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे स्थानीय पश्चास्त को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने देश के कई राज्यों में नदियों के जलस्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण बुलेटिन किया। 6 अगस्त को सुबह 6:39 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार, असम, बिहार, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ का गंभीर खतरा मंडगा रहा है। बिहार के कई जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर में गंगा 60.85 मीटर, पटना के दानापुर में 51.92 मीटर तीव्रघाट में 51.1 मीटर, गांधीघाट में 49.87 मीटर, और हथिदह में 42.74 मीटर पर है, जो सभी खतरे के निशान से ऊपर हैं। भोजपुर, भागलपुर और खगड़िया में भी गंगा का जलस्तर गंभीर स्थिति में है। इसके अलावा, बाया, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, पुनपुन, और धरधा जैसी सहायक नदियां भी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। खगड़िया में कोसी नदी (बलतारा) 34.81 मीटर और कटिहार में 30.73 मीटर पर बह रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां गंभीर स्थिति में हैं। अलकनंदा (रुद्रप्रयाग) 627.6 मीटर और मंदाकिनी (गौरीकुड़) 1976.8 मीटर पर है। हरिद्वार में बाणगंगा और टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर है। झारखण्ड के साहेबगंज में गंगा 27.74 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से 0.49 मीटर ऊपर है। मध्य प्रदेश के दतिया में सिंधं नदी, उत्तर प्रदेश के बदायूं और बाराणसी में गंगा और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा (फरक्का) खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुर्शिदाबाद में गंगा 23.04 मीटर पर है, जो खतरे के निशान से 0.79 मीटर ऊपर है।




ईडी की छापेमारी: 260 करोड़ की साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का भंडाफोड़

नई दिल्ली/एजेंसी

पुर्वतन निवेशालय (ईडी) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तराखण्ड में एक बड़े साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ छापेमारी की। यह कारबाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून के कम 11 टिकानों के निशानों बनाया गया। अनुसार, यह सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली, मामाता के द्वारा जाच व्यूरो नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून जैसे (सीधी आई) और दिल्ली पुलिस शहरों में सक्रिय ठग भारतीय और द्वारा दर्ज की गई एफआई आर का बनाया गया। अनुसार, यह सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली, मामाता के द्वारा जाच व्यूरो नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून जैसे (सीधी आई) और दिल्ली पुलिस शहरों में सक्रिय ठग भारतीय और द्वारा दर्ज की गई एफआई आर का



और अमेजन की तकनीकी सहायता सेवाओं के एजेंट बाबर भी लोगों से ठगी करते थे। ईडी की जांच में पता चला है कि ठगों ने पीड़ितों की धनपरिश को किट्टोरेसी में बदल दिया था और इसे अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। आरोपियों ने कहा कि इन्होंने बॉलेट्स में लाभग्र 260 करोड़ की बिटकॉइन जुटाई थी, जिसे बाद में यूएसडीटी में बदलकर नकदी में तब्दील किया गया। यह बाबर डरते थे और गिफ्टपारी के नाम पर उनसे पैसे ऐंठते थे। इसके और यूई में स्थित व्यक्तियों के अलावा, वे खुले को माइक्रोसॉफ्ट

जांच एजेंसियों के अधिकारी नकदी में तब्दील किया गया। यह बाबर डरते थे और गिफ्टपारी के नाम पर उनसे पैसे ऐंठते थे। इसके और यूई में स्थित व्यक्तियों के अलावा, वे खुले को माइक्रोसॉफ्ट

टेस्ला ने गुरुग्राम में खोला पहला इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर और रिटेल स्टोर

नई दिल्ली/एजेंसी

ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता टेस्ला ने भारत में अपने वित्तान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुरुग्राम के सोहाना रोड स्थित ऑर्किंड बिज़नेस पार्क में 33,475 स्क्वायर फीट का कार्पोरेशनल स्पेस लीज पर लिया है। यह स्पार्क कंपनी ने इस स्पेस के लिए 2,41 करोड़ का सिक्योरिटी डिपोजिट और 40.17 लाख मासिक किराया तय किया है। यह लीज शुरूआती तीन वर्षों तक नॉन-टाइमेनेबल रहेगी और कर्सरम रिटेल स्टोर के रूप में काम करेगा। टेस्ला ने यह लीज ग्रेवल प्राप्टर्ज, ओर्किंड हाईट्रॉफ्टर डेवलपर और सेन्सरी रियल स्टर्ट



के साथ मिलकर साइन की है। लीज समझौता 28 जुलाई को रजिस्टर हुआ और 15 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गया। कंपनी ने इस स्पेस के लिए 2,41 करोड़ का सिक्योरिटी डिपोजिट और 40.17 लाख मासिक किराया तय किया है। यह लीज शुरूआती तीन वर्षों तक नॉन-टाइमेनेबल रहेगी और हर साल किराये में 4.75 फीसदी की वृद्धि मिलता है। जिससे वह अपने अनुसार इंटीरियर डिज़ाइन और सेटअप कर सकती।

भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे डोनाल्ड....द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन कर रहा देश में बंपर कर्माई

मुंबई। अमेरिकी राष्ट्रिय डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार का भारत से गहरा कारोबारी रिस्ता है। हाल ही में अई रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन 2010 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद, उनके संगठन ने भारत में

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय पार्टनर एंजेक्यूटिव को मुताबिक, ट्रंप परिवार का संगठन, द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन, भारत को अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को 10 साल में भारत से कई बड़े और बोगतू जैसे शहरों में बनाए रखा है। यह एक एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किया है, जिसमें गुरुग्राम, एण्ड, मुंबई और कालकता जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संगठन ने 175 मिलियन (1450 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा की कर्माई की है।

अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने भारती

